भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3318
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

नियोजनालयों का उन्नयन

3318. श्री अशोक महादेवराव नेतेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मौजूद नियोजनालयों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सभी नियोजनालयों का 12वीं योजना में यथा परिकल्पित उन्नयन कर दिया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) नियोजनालयों से मॉडल कैरियर सेंटर किस प्रकार भिन्न है; और
(ङ) देश में गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नियोजनालयों के माध्यम से वर्ष-वार और राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआई एंड जीबी) सहित 997 रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

मंत्रालय 2015 से रोजगार से संबंधी विविध सेवाओं को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस परियोजना के तहत, सरकार मौजूदा रोजगार कार्यालयों के उन्नयन सहित आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करने हेतु अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। आदर्श करियर केंद्र एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है तथा इसमें करियर संबंधी सभी सेवाएं जैसे करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार मेले/रोजगार अभियान का आयोजन, तथा इस संबंध में विस्तार की गतिविधियों का संचालन करना आदि प्रदान करने के लिए एक हब के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। ये आदर्श करियर केंद्र, राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से प्रतिकृत किए जा सकते हैं। फिलहाल, सरकार ने 200 आदर्श करियर केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता को अनुमोदन दिया है, जिसमें 175 रोजगार कार्यालय शामिल हैं। राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार एनसीएस परियोजना के इंटरलिंकिंग घटक के तहत राज्य सरकारों को रोजगार मेले आयोजित करने, सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं मौजूदा रोजगार कार्यालयों के नवीनीकरण हेतु अनुदान-सहायता भी प्रदान कर रही है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए गए नियोजन की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-।। पर दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

"नियोजनालयों का उन्नयन" के बारे में पूछे गए श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3318 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एमसीसी में उन्नत रोजगार कार्यालयों का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमसीसी में उन्नत रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1
2	असम	6
3	अंडमान और निकोबार	1
4	आंध्र प्रदेश	8
5	बिहार	11
6	छत्तीसगढ	7
7	दिल्ली	1
8	गोवा	1
9	गुजरात	9
10	हरियाणा	2
11	हिमाचल प्रदेश	2
12	जम्मू और कश्मीर	7
13	लद्दाख	2
14	झारखंड	5
15	कर्नाटक	9
16	केरल	3
17	लक्षद्वीप	1
18	महाराष्ट्र	3
19	मेघालय	2
20	मध्य प्रदेश	8
21	मिजोरम	2
22	नागालैंड	2
23	ओड़िशा	7
24	पुडुचेरी	2
25	पंजाब	4
26	राजस्थान	16
27	तेलंगाना	7
28	त्रिपुरा	3
29	तमिलनाडु	9
30	उत्तर प्रदेश	20
31	उत्तराखंड	4
32	पश्चिम बंगाल	10
	कुल योग	**175**

अनुबंध- II

"नियोजनालयों का उन्नयन" के बारे में पूछे गए श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3318 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उपलब्ध सीमा तक देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित रोजगार मिलने वालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

		नियोजन (संख्या में)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2016**	**2017**	**2018**
1	आंध्र प्रदेश	496	225	241
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0
3	असम	644	842	1022
4	बिहार	1857	258	0
5	छत्तीसगढ	170	465	1008
6	दिल्ली	0	0	0
7	गोवा	1086	0	0
8	गुजरात	330067	394957	342399
9	हरियाणा	439	45	174
10	हिमाचल प्रदेश	1468	735	2507
11	जम्मू और कश्मीर	206	1613	331
12	झारखंड	2510	3536	1428
13	कर्नाटक	677	392	813
14	केरल	11315	8890	9649
15	मध्य प्रदेश	76	0	0
16	महाराष्ट्र	37643	2940	41566
17	मणिपुर	0	493	200
18	मेघालय	8	10	118
19	मिजोरम	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	7
21	ओड़िशा	3831	3861	460
22	पंजाब	2633	2071	1049
23	राजस्थान	52	116	0
24	तमिलनाडु	6183	1752	1157
25	तेलंगाना	452	91	0
26	त्रिपुरा	191	45	66
27	उत्तराखंड	312	61	25
28	उत्तर प्रदेश	1460	962	367
29	पश्चिम बंगाल	1159	4	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	355	0	0
31	चंडीगढ़	152	157	97
32	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पुडुचेरी	93	30	13
	कुल योग	405536	424551	404697

नोट: शून्य आंकड़ों में ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से कोई डाटा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्रोत: रोजगार महानिदेशालय द्वारा संकलित रोजगार कार्यालय सांख्यिकी;

राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एम.ओ.एल. एंड ई।